बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 11

नया संचालन ढांचा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को तीन अन्य वाणिज्यिक बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन (पीसीए) ढांचे से बाहर कर दिया। यानी इन बैंकों को ऋण देने और अन्य बैंकिंग सेवाएं बहाल करने का अवसर मिल गया। इन तीन बैंकों में से इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक सरकारी जबकि धनलक्ष्मी बैंक एक छोटा निजी बैंक है। आरबीआई ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वित्तीय निगरानी बोर्ड (बीएफएस) ने 26 फरवरी को पीसीए के अधीन आने वाले बैंकों के प्रदर्शन के आकलन संबंधी समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया। बीएफएस ने पाया कि सरकार ने 21 फरवरी को पीसीए के ढांचे में आने वाले बैंकों समेत कई बैंकों में नई पूंजी डाली। निश्चित तौर पर दो सरकारी बैंक, जिन्हें पीसीए के ढांचे से बाहर किया गया, वे सरकार द्वारा पुनर्पूंजीकरण के सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभरे। इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को क्रमश: 6,896 करोड़ रुपये और 9,086 करोड़ रुपये की नई पूंजी प्रदान गई। इससे इन बैंकों के पूंजीगत फंड में इजाफा हुआ है और उनके ऋण नुकसान की प्रॉविजनिंग में सुधार हुआ और पीसीए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हुआ।

उम्मीद के मुताबिक ही नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में तीन बैंकों के शेयर सुबह के शुरुआती कारोबार में 10 फीसदी तक उछले। इस महीने के आरंभ में आरबीआई ने तीन अन्य सरकारी बैंकों बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीसीए ढांचे से बाहर कर दिया था और केवल पांच बैंक ही इसमें शेष रह गए थे। यह एक स्वागतयोग्य बात है और उम्मीद की जानी चाहिए कि शेष बैंक भी जल्दी ही अपने मूलभूत काम को अंजाम देने की स्थिति में आ जाएंगे। मूलभूत काम यानी कारोबारियों को ऋण देना और इस तरह देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि अगले छह से आठ महीनों में तीन से चार और बैंक आरबीआई की कमजोर बैंकों की सूची से बाहर हो जाएंगे। यह उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है, पूंजी का स्तर सुधर रहा है और फंसा हुआ कर्ज कम हो रहा है।

सच तो यह है कि ये कमजोर बैंक प्राथमिक तौर पर पीसीए मानकों से पार पाने में इसलिए कामयाब रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनमें बड़े पैमाने पर पूंजी डालने का निर्णय लिया। गत सप्ताह वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि इस वित्त वर्ष में 12 सरकारी बैंकों में 48,239 करोड़ रुपये की नई पूंजी डाली जाएगी ताकि ये नियामकीय पूंजी आवश्यकताओं का ध्यान रख सकें और अपनी वृद्धि योजनाओं को धन मुहैया करा सकें। इस फंडिंग के साथ 1.06 लाख करोड़ रुपये की कुल डाली जाने वाली पूंजी में से 1,00,958 करोड़ रुपये की राशि बैंकों में आ गई। सवाल यह है कि क्या बैंकों को पीसीए से बाहर लाने भर से उनकी बेहतर वृद्धि सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नई पूंजी का एक बड़ा हिस्सा फंसे हुए कर्ज के निपटान में जाएगा और वृद्धि के लिए इस्तेमाल होने वाली पूंजी कम ही रह जाएगी। बैंकों को नए सिरे से ऋण देने की शुरुआत करने के पहले बाजार से धनराशि जुटानी होगी या फिर उनको इस उम्मीद में बजट की प्रतीक्षा करनी होगी कि सरकार शायद और अधिक पूंजी डाले। सरकारी बैंकों के संचालन ढांचे में भी आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। अगर सरकार इस पर ध्यान केंद्रित करती है तो बेहतर होगा। मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचे के अलावा जरूरत यह भी है कि एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जहां उच्च पदों पर नियुक्तियां समय पर हों और बैंकों के बोर्ड पेशेवर और जवाबदेह हों।

विनय सिन्हा

रोजगार सृजन से होगी शांति कायम

कश्मीर घाटी में शांति बहाली में रोजगार सृजन की अहम भूमिका है, हालांकि पुलवामा आतंकी घटना के बाद से इस विषय पर शायद ही कोई बात कर रहा है। विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं नौशाद फोर्ब्स

इस बात से तो सभी सहमत होंगे कि हमारी प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता रोजगार सृजन है। इस समाचार पत्र के विभिन्न पन्नों पर भी पिछले कुछ दिनों के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के भूतपूर्व और वर्तमान सदस्य रोजगार संबंधी अपनी ही रिपोर्ट की सत्यता को लेकर बहस मुबाहिसा करते नजर आए हैं। ऐसी खबरें सुर्खियों में रही हैं जहां सरकार में शामिल लोग रोजगार सृजन की बात करते नजर आए जबकि विपक्षी दल रोजगार समाप्त होने या कम होने की दुहाई देते दिखे। यह सिलसिला उस समय थम गया जब पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों पर आतंकी हमला हुआ। तब से लेकर अब तक अखबार और टेलीविजन दोनों जगह इस आतंकी हमले से जुड़ी घटनाओं का ही बोलबाला है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के ऐन पहले तक यह आलेख पूरी तरह रोजगार के बारे में होना था लेकिन अब यह कश्मीर से संबंधित है। ऐसा लग रहा है मानो रोजगार तो फिर भी प्रतीक्षा कर सकते हैं और वह मुद्दा बाद में उठाया जा सकता है।

यह आलेख पुलवामा में हुए आतंकी हमले में मारे गए सीआरपीएफ के 40 जवानों के बारे में नहीं है। इन नौजवानों को असमय काल के गाल में समाना पड़ा, उनके परिवारों पर विपदा टूट पड़ी। यह आलेख संभावित बदले के बारे में भी नहीं है, जिसके परिणाम और अधिक त्रासद हो सकते हैं। एक और बात, यह आलेख प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद का जाप करने वाली राजनीति से भी कतई संबंधित नहीं है। यह आलेख उस त्रासदी के बारे में है जिसका नाम ही कश्मीर है। कश्मीर घाटी किसी भी मानक पर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। श्रीनगर, गुलमर्ग या पहलगाम का भौगोलिक सौंदर्य तथा लकड़ी का काम, कारपेट एवं कढ़ाई का काम आदि जम्मू कश्मीर को पर्यटन की दृष्टि से स्वर्ग बनाते हैं।

जब हम बच्चे थे तो छुट्टियां मनाने की दृष्टि से कश्मीर हमारे परिवार की पसंदीदा जगह हुआ करती थी। सन 1989 तक हम निरंतर कश्मीर जाया करते थे। उसके बाद सन 2011 तक यह सिलसिला बाधित रहा। सन 2011 के बाद हमने कश्मीर की तीन यात्राएं कीं। कुछ वर्ष पहले तक ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक कश्मीर घाटी का रुख कर रहे थे। इस बात का फायदा कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा था। दो दशक में पहली बार कश्मीर घाटी में रोजगार के अवसर तैयार हो रहे थे और युवाओं में भविष्य को लेकर उम्मीद जाग रही थी।

सन 2011 और 2011 में 12 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने उड़ान नामक एक शानदार पहल की। इसके तहत कश्मीर के हजारों एमबीए और इंजीनियरिंग छात्रों को मुंबई और पुणे के उद्योगों की यात्रा कराई गई। हमारे जैसे जिन लोगों ने अपनी कंपनियों में इन बच्चों की मेजबानी की उन्हें यही लगा होगा कि छात्र हमारी प्रौद्योगिकी देखकर प्रसन्न हुए और हमने अपने प्रबंधन की योग्यता से उन सभी को प्रभावित किया। परंतु उन्होंने हमें बताया कि उन्हें अपने जीवन में पहली बार शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स आदि देखकर सबसे अधिक आनंद आया।

यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अधिकांश इंसानी आबादी सबसे पहले अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। वे अच्छी आजीविका, संतोषजनक रोजगार और ऐसा भविष्य चाहते हैं जो उनके बच्चों को उनसे बेहतर जीवन दे सके। सन 2012 में सीआईआई के छात्र संबंधी कार्यक्रम के बाद हमारी पहली श्रीनगर यात्रा में मेरे भाई ने और मैंने पुणे में हमारे साथ काम करने के लिए करीब छह कश्मीरी एमबीए छात्रों का साक्षात्कार लिया।

हमारी बातचीत ऐसे मोड़ पर आ गई जहां हमने उनसे पूछा कि वे भारत, पाकिस्तान और कश्मीर को कैसे देखते हैं। उनका जवाब एकदम स्पष्ट था: सभी बच्चों को अपना भविष्य भारत के साथ नजर आ रहा था। इसके लिए कोई नैतिक वजह या सन 1947 के पहले की कोई वैधानिक स्थिति जिम्मेदार नहीं थी। इसकी एकमात्र वजह भारतीय अर्थव्यवस्था थी। उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था फलफूल रही थी। उन्हें हमारे साथ ऐसा भविष्य नजर आ रहा था जिसका वे हिस्सा बनना चाहते थे। पाकिस्तान पर वे विचार ही नहीं कर रहे थे। अब हमारे भीतर का राष्ट्रवाद इस बात को लेकर क्रुद्ध हो सकता है कि वे आर्थिक अवसरों की वजह से हमारी ओर आकृष्ट थे। परंतु ध्यान रहे कि उनका आकर्षण कहीं अधिक वास्तविक और मजबूत था।

यह वही भावना है जिसके चलते भारत में जन्मे लेकिन अब अमेरिका में रहने वाले लोगों की संख्या सन 1980 के 10 लाख से बढ़कर आज 30 लाख तक पहुंच गई है। इनमें से अधिकांश तो अब अमेरिका की नागरिकता भी ग्रहण कर चुके हैं। उनकी आर्थिक सफलता की बदौलत ही आज देश के कुछ बड़े राष्ट्रवादी संगठनों की फंडिंग होती है। राष्ट्रवाद को आर्थिक संभावनाओं और अवसरों से जोड़ने वाली यह भावना अत्यंत ताकतवर है।

हमने एमबीए के जिन छात्रों का साक्षात्कार किया वे कोई सामान्य रूढ़िवादी बच्चे नहीं थे। उनकी शिक्षा और सीआईआई की पहल की बदौलत वे घाटी के 5 फीसदी भाग्यशाली बच्चों में शामिल थे जबकि उनके 95 फीसदी अन्य भाई-बंधुओं की तकदीर उनके जैसी नहीं थी।

परंतु कश्मीर समस्या का दीर्घकालिक हल इसी में निहित है। कश्मीर में अच्छे स्कूल और कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता है ताकि बेहतर मानव संसाधन तैयार हो और उनको बेहतर मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। राजनीतिक तौर तरीकों में बदलाव के जरिये कश्मीर घाटी में शांति बहाली का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि हजारों की संख्या में पर्यटक आएं और वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। कश्मीरी छात्रों के लिए देश भर के स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाने चाहिए। उद्योग जगत को बड़ी तादाद में कश्मीरी स्नातकों को अपने यहां जगह देनी चाहिए। एक ऐसे चुनाव प्रचार अभियान की आवश्यकता है जो कश्मीरियों समेत देश के 95 फीसदी लोगों के लिए अवसर तैयार करने की बात कहता हो। रोजगार के अवसर लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

(लेखक फोर्ब्स मार्शल के को-चेयरमैन, सीआईआई के पूर्व प्रेसिडेंट और सीटीआईईआर के चेयरमैन हैं। लेख में प्रस्तुत विचार निजी हैं।)

राजकोषीय मोर्चे पर बेहतर योगी सरकार का प्रदर्शन

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्ववादी राजनीति के चलते प्राय: खबरों में रहते हैं। लेकिन उनकी सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन पर बहुत कम ध्यान ही दिया गया है। यहां तक कि उनकी सरकार के नवीनतम बजट के बारे में भी अखबारों में सुर्खियां यही बनी कि योगी सरकार ने गायों के आश्रयस्थल बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। योगी सरकार के इस तीसरे बजट में राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में कम ही चर्चा हुई है।

इसकी वजह यह नहीं है कि राज्य के बजट के बारे में ब्योरा आसान फॉर्मेट में तत्काल मुहैया नहीं हो पाता है। राज्यों में बजट पेश होने के कई महीने बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) राज्यों के बजट के बारे में अपना वार्षिक प्रकाशन लाता है। उसके बाद ही राज्य के बजट के बारे में कोई समुचित विश्लेषण किया जा सकता है जिसमें राजस्व और व्यय के मोर्चे पर पिछले साल की तुलना में अध्ययन किया जा सके। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट इस खाई को भरने की कोशिश करती है। इसमें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अब तक आठ राज्यों में पेश बजटों का ब्योरा दिया गया है।

यह रिपोर्ट योगी सरकार के बारे में लोकप्रिय धारणा के उलट नजरिया पैदा करती है। इस सरकार के तीनों बजट बताते हैं कि राज्य ने राजकोषीय मजबूती की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार के अंतिम वित्त वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.5 फीसदी रहा था। लेकिन योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वित्त वर्ष 2017-18 में इसे 2.02 फीसदी पर ला दिया। ये दोनों ही आंकड़े वास्तविक हैं और ऑडिट जांच से गुजर चुके हैं। योगी सरकार के दूसरे बजट 2018-19 में संशोधित अनुमानों के मुताबिक राजकोषीय घाटा थोड़ा बढ़कर 2.97 फीसदी हो गया था। वर्ष 2019-20 के बजट में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने राजकोषीय घाटे के जीएसडीपी का 2.97 फीसदी ही रहने का अनुमान जताया है। वित्त आयोग ने राज्यों में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन फीसदी के दायरे में तय किया हुआ है और उत्तर प्रदेश भी अब गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद इस सीमा के भीतर रहने वाला राज्य बन चुका है। राज्य के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के फासले यानी राजस्व संतुलन के बारे में क्या स्थिति है? इस मामले में भी उत्तर प्रदेश अधिशेष स्थिति हासिल कर चुके गिने-चुने राज्यों में शामिल हो चुका है। राजस्व अधिशेष 2017-18 में जीएसडीपी के 0.91 फीसदी पर खिसक आया था लेकिन 2018-19 में यह बढ़कर 3.2 फीसदी पर जा पहुंचा था। हालांकि अगले वित्त वर्ष में अधिशेष के 1.76 फीसदी ही रहने का अनुमान जताया गया है।

ऐसा हो पाने की संभवत: बड़ी वजह यह है कि राज्य के अपने कर राजस्व में तीव्र वृद्धि हुई है। योगी सरकार के पहले साल में उत्तर प्रदेश का अपना कर राजस्व वर्ष 2017-18 में 8 फीसदी बढ़कर 97,393 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। लेकिन 2018-19 में 38 फीसदी की नाटकीय उछाल होने से राज्य सरकार का कर राजस्व 1.34 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। जिस तरह 2018-19 में हुई जबरदस्त उछाल चौंकाने वाली है, कुछ उसी तरह 2019-20 में कर राजस्व में महज 4 फीसदी वृद्धि होने का अनुमान भी अचंभित करता है।

क्या यह उछाल उत्तर प्रदेश के अपने कर राजस्वों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के पहले पूर्ण वर्ष का नतीजा थी? और अब जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाए जाने और उनमें कटौती के बाद कई क्षेत्रों को नई रियायतें दी जा चुकी हैं जिससे कर राजस्व में वृद्धि धीमी ही रहने के आसार हैं। वर्ष 2018-18 में उत्तर प्रदेश के लिए जीएसटी राजस्व 1.06 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान था और 2019-20 में इसमें तीन फीसदी बढ़ोतरी का ही अनुमान है। अगर आने वाले वर्षों में जीएसटी संग्रह में सुस्ती आने से उसके कर राजस्व में वृद्धि स्थिर होती है तो राज्य सरकार के लिए यह निश्चित रूप से एक चुनौती होगी।

योगी सरकार के कार्यकाल में ध्यान देने लायक एक और बात उसके पूंजीगत व्यय से जुड़ी हुई है। यह 2018-19 में 110 फीसदी की जबरदस्त उछाल के साथ 1.17 लाख करोड़ रुपये जा पहुंचा जबकि 2017-18 में यह 55,599 करोड़ रुपये था। वर्ष 2019-20 में पूंजीगत व्यय के मामली गिरावट के साथ 1.16 लाख करोड़ रुपये रहने के अनुमान जताए गए हैं। सरकार के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 2017-18 के 17 फीसदी से बढ़कर 2018-19 में 26 फीसदी पर जा पहुंची और अगले वित्त वर्ष में इसके 24 फीसदी पर रहने का अनुमान है। राज्य के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी को चौथाई स्तर तक पहुंचाना एक ऐसी उपलब्धि है जो बहुत कम राज्य ही हासिल कर पाए हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने उत्तर प्रदेश के लिए पूंजी परिव्यय का भी गणना की है और इसे पूंजीगत व्यय के एक ऐसे अवयव के तौर पर परिभाषित किया है जिसका प्रत्यक्ष इस्तेमाल परिसंपत्ति निर्माण में होता है। इस तरह का पूंजी परिव्यय भी 2018-19 में दोगुना होकर 88,528 करोड़ रुपये रहा है और 2019-20 में इसके आंशिक गिरावट के साथ 77,641 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। दूसरे शब्दों में, योगी सरकार ने अपने बजटों में पूंजी व्यय से होने वाले परिसंपत्ति निर्माण को नजरअंदाज नहीं किया है। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी आकार 14.76 लाख करोड़ रुपये है और इस वजह से वह पांच शीर्ष राज्यों में शामिल है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से भी एक है। लेकिन अगर राज्य राजकोषीय समझदारी दिखाता है और परिसंपत्ति निर्माण पर अधिक खर्च करता है तो वह राजकोषीय मोर्चे पर कुछ सही कदम तो उठा ही रहा है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि आर्थिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश के राजकोषीय प्रदर्शन पर गौर करें? इससे राज्य में आर्थिक वृद्धि की संभावना के बारे में बेहतर समझ पैदा करने में मदद मिलेगी।

कानाफूसी

जोश का कारोबार

जब भावनाएं उबाल पर होती हैं तो ब्रांड भी बाजार में ऐसे अवसरों का लाभ उठाने से नहीं चूकते। फास्ट फूड रेस्टोरेंट बर्गर सिंह जिसने 2016 में उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद अंजाम दी गई सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त छूट की पेशकश की थी, उसने मंगलवार को बालाकोट में भारत की हवाई कार्रवाई के बाद दोबारा छूट की बात कही। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले की खबर आने पर रेस्टोरेंट ने अपने ग्राहकों को 'एफपाकअगेन' कूपन के माध्यम से 20 फीसदी की छूट देनी शुरू कर दी। उसने 2016 में 30 फीसदी तक की छूट प्रदान की थी। दोनों ही मौकों पर उसे सोशल मीडिया पर असंवेदनशील होने का उलाहना सहना पड़ा। पुणे में निजी बीमा कंपनी बजाज आलियांज लाइफ ने अपने कार्यालय के बाहर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॉल बोर्ड पर लिखा- 'हाऊ इज द जोश?' उसने यह संवाद उड़ी : द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म से लिया।

बाबर के वारिस

विनय सिन्हा

मंगलवार को रंगीन शेरवानी और उससे मेल खाती हुई पगड़ी पहने हुए एक व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। उसका दावा है कि वह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की छठी पीढ़ी का वंशज है। प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तकी ने देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख करते हुए कहा कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद में उसका पक्ष भी सुना जाए। उसने दावा किया कि जिस जमीन पर विवादित बाबरी मस्जिद बनी है, उसका मालिकाना हक उनका है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचिका सुनने से इनकार कर दिया लेकिन उन्हें सुनवाई के बाद अपने वकीलों से अत्यंत उत्सुकतापूर्वक बात करते देखा गया। वह अधिवक्ताओं के साथ सेल्फी लेते हुए भी देखे गए।

आपका पक्ष

आतंकवाद खत्म करने का आगाज

भारतीय वायु सेना ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों का बदला पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को तबाह कर ले लिया। महज 20 मिनट में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर भारतीय सेना ने दिखा दिया कि देश की तरफ बुरी नजर रखने वाले दुश्मनों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना ने यह भी दिखा दिया कि अगर सेना को कुछ छूट दे दी जाए तो वह जैश-ए-मोहम्मद, अलकायदा जैसे हर एक आतंकवादी संगठन का खात्मा कर सकती है। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद देश की जनता में आक्रोश का माहौल है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार को इस कार्रवाई के खिलाफ फैसला लेने में काफी आसानी हुई। वहीं केंद्र सरकार ने सेना को इस कार्रवाई के लिए मंजूरी देकर शहीद हुए जवानों का मान रखा और यह संदेश दिया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से शांति वार्ता के लिए एक और मौका देने का आग्रह किया था, लेकिन भारत ने वायुसेना की कार्रवाई से पाकिस्तान को जवाब दे दिया है।

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर हवाई अड्डा हाई अलर्ट पर रहा

यह भी संदेश दिया गया है कि आतंकवाद के पनाहगारों के साथ भारत किसी तरह का कोई वार्ता नहीं करेगी।

शुभम शर्मा, नोएडा

युद्ध नहीं आतंकवाद का हो खात्मा

पुलवामा में आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी संगठनों के ठिकाने पर बम बरसाए। भारत के इस कदम से पाकिस्तान भी कार्रवाई करने की चेतावनी दे चुका है। हालांकि भारत का वार आतंकवाद पर है लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी सेना का इस्तेमाल करता है तो युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। आतंकवाद को खत्म करने के लिए युद्ध कोई उपाय नहीं है। दोनों देशों को युद्ध से बचना चाहिए तथा आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में कारगर पहल करनी चाहिए। इससे युद्ध से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

नकली शराब कारोबार बंद हो

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा कुशीनगर जिले में जहरीली शराब के सेवन से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद असम में भी जहरीली शराब पीने से करीब 85 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मृतकों की संख्या में इजाफा संभव है क्योंकि घटना के बाद करीब 300 पीड़ित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकार ने इस मामले में सक्रियता दिखाई है और पीड़ित लोगों को चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सवाल यह है कि लोगों के बीच जहरीली शराब कहां से पहुंचती है। ऐसी घटना के पीछे कौन लोग हैं तथा घटना के जिम्मेदार कौन हैं। सरकार को घटना के दोषियों का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा नकली शराब के कारोबार को खत्म करने के लिए अलग व्यवस्था बनानी चाहिए।

दुर्गेश शर्मा, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।